"डी. एस. तेवतिया और एम. आर. अग्निहोत्री, जस्टिस

भारतीय खाद्य निगम, –प्रार्थी

विरुद्ध

प्रेसाइडिंग ऑफिसर, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालय, और अन्य,–

प्रतिवादी

सिविल रिट पीटीशन संख्या 4384 का 1986

8 अप्रैल, 1987

"औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV)–धारा 25-एफ–कॉन्ट्रैक्ट श्रम (नियामक और उन्मूलन) अधिनियम (1970 का XXXVII)–धाराएँ 7, 9, 12 से 20, 29–मुख्य नियोक्ता द्वारा कार्यकर्ता का निष्कासन–मुख्य नियोक्ता द्वारा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी को नकारना क्योंकि कार्यकर्ता एक श्रम ठेकेदार के माध्यम से रोजगार में था–ऐसे कार्यकर्ता–क्या कार्यकर्ता के रूप में गिना जाएगा–निर्धारण के लिए शर्त।"

"निर्णय, कि हर कार्यकर्ता जो किसी मुख्य नियोक्ता के लिए काम करता है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट श्रम (नियामक और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान लागू होते हैं, उसे मुख्य नियोक्ता का कार्यकर्ता माना जाना चाहिए, यहां तक कि जब तक दो शर्तें पूरी न हों: –

(i) कि संचालन के लिए एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था अधिकारी अवधि के लिए; और

(ii) कि लाइसेंस ठेकेदार के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त किया था।"

अगर दोनों में से कोई एक शर्त अनुपस्थित है तो ठेकेदार के माध्यम से नियोक्ता द्वारा नियुक्त श्रमिक को कार्यकर्ता के रूप में माना जाएगा।

(पैरा 11)

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि रिट पीटीशन को स्वीकार किया जाए, मामले के रिकॉर्ड भेजे जाएं; और

(i) प्रार्थना पत्र पर आपत्तिजनक पुरस्कृत पत्र P / 12 को रद्द करने के लिए एक certiorari के स्वरूप में एक रिट जारी की जाए;

(ii) इस मामले के परिस्थितियों में जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझता है, उस पर अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(iii) यहां तक कि प्रार्थना किए गए पुरस्कृत अवार्ड से अनवाद्य हो चुका है और इसके अलावा उत्तरदाता संघ ने इस माननीय न्यायालय में पहले ही एक caution दाखिल कर दी है, इसलिए notice of motion की सेवा माफ की जाए।"

(iv) Annexures P/l से P/13 तक के मूल / प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की जरूरत नहीं है;

(v) आपत्तिजनक अवार्ड के प्रचालन को रोका जाता है, जब तक कि यह माननीय न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया जाता है; और

(vi) पेटीशनर को लागत दी जाए।

न. के. सोधी, वरिष्ठ वकील, (उनके साथ आर. एन. रैना, वकील),

-प्रार्थियों के लिए

जी. सी. गुप्ता, वकील

-प्रतिवादी के लिए

फैसला

डी. एस. तेवतिया, जे।

1. भारतीय खाद्य निगम द्वारा दायर तीन रिट पिटीशन (सी.डब्ल्यू.पी. 4384, 4857 और 4894 ऑफ 1986) जो एक समान अवार्ड को चुनौती देते हैं, जो 27 मार्च, 1986 को केंद्र सरकार, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ (जिसे इसके बाद 'ट्रिब्यूनल' कहा जाता है) द्वारा दिया गया है, समान कानूनी और तथ्य के प्रश्नों को शामिल करते हैं, और इसलिए समान फैसला प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. प्रार्थी भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में 'निगम') अधिनियम द्वारा गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्यत: पूरे देश में खाद्य अनाज की प्राप्ति, भंडारण और वितरण करना था। यह निगम अपने मुख्यालय के माध्यम से दिल्ली में और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता था। निगम के नॉर्दन जोन में पंजाब क्षेत्र और हरियाणा क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्यालय थे। निगम ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए हजारों हैंडलिंग मज़दूरों को संबोधित करने के लिए नियुक्त किया था, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उसके ठेकेदारों के माध्यम से लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य करते थे। निगम और कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच विवाद उत्पन्न हुआ जो पंजाब क्षेत्र के अमृतसर डिपो और नवांशहर डिपो और हरियाणा क्षेत्र के अंबाला डिपो में उनकी दी गई गतिविधियों को संचालित करने के लिए निगम द्वारा नियुक्त किया गया था। इन तीन डिपोटों के सभी कर्मचारियों ने यह दावा किया कि वे निगम के कर्मचारी थे और उनकी सेवाएं अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त की जा रही थीं। ये तीन विवाद आखिरकार चंडीगढ़ में ट्रायल होने के लिए आए। निगम ने सख्ती से ट्रायल के पहले अपना दावा रखा कि उनके कार्यकर्ता उनके नहीं थे क्योंकि उन्हें उनके ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया गया था, जो वास्तविक रूप से उनके काम और आचरण पर प्रभावी नियंत्रण रखते थे; कि कर्मचारियों का निगम की फर्जी में नहीं था और कार्यकर्ता और निगम के बीच सम्बंध की कमी के कारण निगम को उनकी नियुक्ति के समापन के संबंध में जवाबदेही नहीं थी। अपने मामले

की समर्थन में, निगम ने साक्ष्य-बक्स में सहायक प्रबंधक श्री कृष्ण लाल (एमडब्ल्यू-1) और उप प्रबंधक श्री ए. के. कोली (एमडब्ल्यू-2) आदि को बुलाया था।

3. संविष्ट तथ्यों के आधार पर ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष यह निकला कि कॉर्पोरेशन एक 'उद्योग' था जैसा कि धारा 2(i) के अनुसार परिभाषित था, और इसके लिए, ठेकेदार श्रम (नियंत्रण और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (जिसे यहाँ 'ठेकेदार श्रम अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधान भी लागू थे; कॉर्पोरेशन ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पंजीकृत नहीं था और न ही वह लाइसेंस प्राप्त करने वाले ठेकेदारों को नियोक्ता बनाता था, इसलिए अनुमानित ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के रूप में देखा जाना चाहिए और उनकी सेवाओं का समापन अनुमानित ठेकेदारों द्वारा किया गया उनके स्वयं कोर्पोरेशन द्वारा किया गया माना जाना चाहिए, और यह कि यह कानून की धारा 25-एफ के प्रावधानों का उल्लंघन करके हुआ था, और इसलिए उनकी सेवाओं का समापन स्पष्ट रूप से अवैध था।

4. उपर्युक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत, त्रिब्यूनल ने कॉर्पोरेशन को आदेश दिया कि वह कर्मचारियों को तत्काल उनकी मूल पदों पर पुनः स्थापित करे और उनकी सामान्य वेतन का तत्काल प्रभाव से भुगतान शुरू करे।

5. कॉर्पोरेशन (याचिककर्ता) ने उक्त पुरस्कार को चुनौती देने के लिए तीन अलग-अलग रिट पिटीशन्स (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4384/1986, सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4857/1986 और सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4894/1986) दायर की हैं, जो कि संदर्भ I.D. संख्या 49/1984, संदर्भ I.D. संख्या 157/1983 (दिल्ली), I.D. संख्या 12/1983 (चंडीगढ़) और संदर्भ I.D. संख्या 112/1983 से प्राप्त हुईं हैं।

6. कॉर्पोरेशन के वकील ने ट्रिब्यूनल की निम्नलिखित दो फैसलों पर ही आपत्ति दर्ज की है-

   (i) कि कॉर्पोरेशन ने श्रम ठेकेदार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार खुद को पंजीकृत नहीं कराया था; और

(ii) कि कुछ कर्मचारियों को मासिक वेतन कोर्पोरेशन द्वारा भुगतान किया जाता था बिना कि ठेकेदार के मध्यस्थ एजेंसी के साथ, जैसा कि प्रमाणपत्र डब्ल्यू-3 और डब्ल्यू-8 के रूप में दर्शाया गया था, जिनकी मान्यता कोर्पोरेशन की ओर से स्वीकृत की गई थी।

पहले फैसले के संबंध में, रिट पिटीशन में यह दावा किया गया है कि वास्तव में पंजीकरण प्रमाण पत्र कॉर्पोरेशन द्वारा प्राप्त किया गया था और इसकी प्रतिलिपि त्रिब्यूनल के रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई थी जो कि प्रमाण M-44 के रूप में था और इसकी एक प्रतिलिपि रिट पिटीशन के Annexure P-13 के रूप में संलग्न की गई है।

दूसरे फैसले के संबंध में, इसमें उल्लेख किया गया है कि अनुमानित दस्तावेज पंजाब क्षेत्र से संबंधित थे और वे कॉर्पोरेशन के हरियाणा क्षेत्र से संबंधित नहीं थे।

7. यह विवादरहित है कि ठेकेदार श्रम अधिनियम की धाराएं कॉर्पोरेशन पर लागू होती हैं, अर्थात, अगर कॉर्पोरेशन किसी ठेकेदार को नियोजित करना चाहता है, तो उसे ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 7 के तहत खुद को पंजीकृत करवाना होगा, जिसका प्रावधान निम्नलिखित है:

"धारा 7: कुछ स्थापनाओं का पंजीकरण।–(1) इस अधिनियम लागू होने वाली किसी स्थापना के प्रमुख नियोक्ता को इस प्रसंग में, जैसा कि सूचना के माध्यम से उपयुक्त सरकार द्वारा सामान्य रूप से या उनमें से किसी वर्ग के साथ इसके लिए निर्धारित किया गया हो, उस समय के भीतर पंजीकरण अधिकारी के पास निर्धारित तरीके से स्थापना के पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए:

परन्तु, यदि पंजीकरण अधिकारी संतोषजनक कारण से प्रमाणित होता है कि आवेदक ने समय पर आवेदन करने से रोका गया था, तो उस प्रावधान के बाद भी उसकी पंजीकरण के लिए कोई ऐसा आवेदन स्वीकार कर सकता है।"

2. यदि पंजीकरण के लिए आवेदन सभी प्रतियोगिताओं में पूर्ण है, तो पंजीकरण अधिकारी को स्थापना को पंजीकृत करना चाहिए और स्थापना के प्रमुख नियोक्ता को पंजीकरण की प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए, जिसमें ऐसे विवरण शामिल हों जैसा कि प्रावधानिक हो।

“ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 9 असंगति का प्रभाव व्यक्त करती है। इस प्रावधान में निम्नलिखित है:

"धारा 9: अपंजीकरण का प्रभाव.– जिस स्थापना के प्रमुख नियोक्ता को इस अधिनियम लागू होता है, उसके मामले में–

(i) वह कोई स्थापना जिसे धारा 7 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन जो उस धारा के तहत निर्धारित समय में पंजीकृत नहीं हुई है।

(ii) उस स्थापना के मामले में जिसकी पंजीकरण को धारा 8 के तहत वापस ले लिया गया है। इस प्रकार के मामले में, वह स्थापना किसी भी ऐसे कारण के बाद ठेकेदार श्रम को स्थापना में नियोक्ता नहीं करेगा, जो श्रेणी (अ) में संदर्भित समय के समापन के बाद होता है या श्रेणी (ब) में संदर्भित पंजीकरण के वापस लिए जाने के बाद होता है।"

उपर्युक्त धारा 9 की विधियों का परीक्षण दिखाएगा कि किसी भी स्थापना के प्रमुख नियोक्ता, जिसे ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 7 के तहत पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है या उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वापस लिया जाता है, तो उस प्रमुख नियोक्ता को श्रेणी (अ) और श्रेणी (ब) में उक्त समयावधि के बाद स्थापना में कोई भी ठेकेदार श्रम नियोक्ता नहीं करना चाहिए।

8. ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रावधान किया गया है कि कोई भी ठेकेदार ठेकेदार श्रम के तहत किसी भी काम को संविदा श्रम के

माध्यम से संपादित या कार्यान्वित नहीं करेगा, बिना इसके लिए और उसके अनुसार प्राप्त लाइसेंस के तहत जारी किए जाने वाले लाइसेंस द्वारा। ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 12 का संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है:–

> "धारा 12: ठेकेदारों का लाइसेंसिंग।–(1) उस तारीख से प्रभावी होकर, जो सूचना के माध्यम से उपयुक्त सरकार द्वारा सूचना जारी करेगी, किसी भी ठेकेदार को जिस पर यह अधिनियम लागू हो, ठेकेदार श्रम के माध्यम से किसी भी काम को संपादित या कार्यान्वित नहीं करना चाहिए, बिना इसके लिए और उसके अनुसार प्राप्त लाइसेंस के तहत जारी किए जाने वाले लाइसेंस द्वारा।
>
> (2) इस अधिनियम की प्रावधानिकता के अनुसार, उपधारा (1) के अंतर्गत दी गई लाइसेंस में, विशेष रूप से काम के समय, वेतन की निर्धारण और संविदा श्रम के अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में, उचित सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वहां शामिल ऐसी शर्तें हो सकती हैं, जिन्हें लागू करना उचित समझा जाता है, और यह लाइसेंस वह शुल्क का भुगतान करके और जो भी रकम निर्धारित हो, जो नियमित रूप से इन शर्तों की नियमित पालना के लिए सुरक्षा के रूप में जमा की जाती हो, उसे निर्धारित नियमों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।

ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 13 में लाइसेंस की प्रदान के लिए होती है और ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 14 में लाइसेंस के रद्द, निलंबन और संशोधन की प्रक्रिया को विचार में लाती है। ठेकेदार श्रम अधिनियम की धाराएं 16, 17, 18 और 19 में संविदा श्रम का उपयोग करने वाले स्थापना में श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाती है। ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 20 में प्रमुख नियोक्ता को अंतिम रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है कि धारा 16 से 19 तक की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता। ठेकेदार श्रम

अधिनियम की धारा 21 में प्रमुख नियोक्ता को श्रमिकों को वेतन देने के लिए जिम्मेदारी थोपी गई है अगर ठेकेदार ऐसा नहीं करता। बेशक, दोनों मामलों में प्रमुख नियोक्ता को ठेकेदार से पूर्तिवद्ध करने का अधिकार होता है।

9. ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 29 निम्नलिखित है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि प्रमुख नियोक्ता को ऐसे पंजीकरण और रिकॉर्ड बनाने का अधिकार होगा जो संविदा श्रम को नियोक्त किया जाएगा, संविदा श्रम द्वारा किया जाने वाले काम की प्रकृति, संविदा श्रम को दिया जाने वाला वेतन और ऐसे अन्य विशेषताओं का विवरण देगा, जैसा कि नियमों द्वारा प्रतिनिधित किया जाएगा: –

"धारा 29: रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड बनाए जाने की व्यवस्था.–(1) प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता और प्रत्येक ठेकेदार को ऐसे पंजीकरण और रिकॉर्ड बनाने का अधिकार होगा जो संविदा श्रम को नियोक्त किया गया हो, संविदा श्रम द्वारा किया जाने वाले काम की प्रकृति, संविदा श्रम को दिया जाने वाला वेतन और ऐसे अन्य विशेषताओं का विवरण देगा, जैसा कि नियमों द्वारा प्रतिनिधित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता और प्रत्येक ठेकेदार को ऐसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जैसा कि नियमों द्वारा प्रतिनिधित किया जाएगा, संविदा श्रम को नियोक्त किया जाने वाले स्थान के संस्थान में जहां संविदा श्रम काम कर रहा हो, निर्धारित रूप में नोटिस दिखाने का अधिकार होगा जिसमें काम के समय, कार्य की प्रकृति और निर्धारित अन्य जानकारियां हों।

10. कॉर्पोरेशन ने पूरी तरह से इस तथ्य के बारे में अनजानी बखूबी दिखाई दी कि कौन-कौन से व्यक्ति ठेकेदार द्वारा नियोक्त हुए थे। उसने यह भी पूरी तरह से अनजानी दिखाई कि क्या कॉर्पोरेशन द्वारा ठेकेदारों द्वारा रोजगार किए जाने वाले व्यक्तियों के पास ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आवश्यक लाइसेंस था या नहीं। हमारे दृष्टिकोण

से ऐसी अनजानी धारा 29 की ठेकेदार श्रम अधिनियम की प्रावधानिकता के प्रकाश में अस्वीकार्य है। कॉर्पोरेशन ने अनजानी बखूबी दिखाकर त्रिब्यूनल से उन तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जो उसके खिलाफ हो सकते थे।

11. हमारे विचार से, हर कार्यकर्ता जो ठेकेदार श्रम अधिनियम की प्रावधानिकता लागू होने वाले प्रमुख नियोक्ता के लिए काम करता है, उसे प्रमुख नियोक्ता का कार्यकर्ता माना जाना चाहिए, जब तक दो शर्तें पूरी न हों: –

(i) कि संस्थान ने संबंधित अवधि के लिए पंजीकरण प्राप्त किया था; और

(ii) वह ठेकेदार के माध्यम से संविदा श्रम को नियोक्ता किया था।

यदि इनमें से कोई एक शर्त भी अनुपस्थित है, तो ठेकेदार के माध्यम से नियोक्त किये गए संविदा श्रम को "कार्यकर्ता" के रूप में देखा जाएगा।

12. वर्तमान मामले में, कॉर्पोरेशन द्वारा त्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया सकारात्मक तर्क यह था कि कार्यकर्ता ठेकेदार के कर्मचारी थे और वे उसके (कॉर्पोरेशन के) कर्मचारी नहीं थे। कॉर्पोरेशन को केवल तब ही कोई उत्तरदायित्व नहीं था यदि उसने सिद्ध किया कि कार्यकर्ता लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा नियुक्त हुए थे। कॉर्पोरेशन ने त्रिब्यूनल के समक्ष उस तथ्य को स्थापित नहीं किया था।

13. क्या कॉर्पोरेशन ने ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पंजीकरण प्राप्त किया था या नहीं, इस सवाल के संबंध में यह देखा जा सकता है कि प्रमाण पत्र, एक्सहिबिट पी-13, कोई तारीख नहीं दर्शाता है, तो हमें यह अनुमान करना पड़ता है कि यह कब प्राप्त किया गया था और यह किस अवधि के लिए संबंधित था। डिप्टी मैनेजर, फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, का शपथपत्र, एक्सहिबिट पी-9, भी नहीं उल्लेख करता कि वह संबंधित अवधि के लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया था या नहीं।

14. तर्क के लिए, जैसा पहले ही देखा गया है, यदि कॉर्पोरेशन के पास आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी था, तो भी यह नहीं बच सकता कि

वह ठेकेदार द्वारा नियोक्त किए गए कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपनी जिम्मेदारी से बचें, जब तक यह भी स्थापित न करें कि प्रमुख नियोक्ता द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोक्त किए गए कॉन्ट्रैक्टर के पास ठेकेदार श्रम अधिनियम की धारा 12 की अनिवार्य लाइसेंस थी। कॉर्पोरेशन (याचिककर्ता) ने यह स्थापित करने में विफल रहा है, जैसा पहले से ही देखा गया है।

15. पूर्वोक्त कारणों के लिए, हमें इन याचिकाओं (सीडब्ल्यूपी नंबर 4384, सीडब्ल्यूपी नंबर 4857 और सीडब्ल्यूपी नंबर 4894 ऑफ 1986) में कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दी और हम इसे लागत के संबंध में कोई आदेश के बिना खारिज कर रहे हैं।

एस.सी.के.

मुख्य न्यायाधीश एच.एन. सेठ और एम.एस. लिबरहान, न्यायाधीश के समक्ष।

एम/एस लीडर वाल्व्स (पी) लिमिटेड,–याचिककर्ता

विरुद्ध

कमिश्नर, आयकर, जुलंदर और अन्य,–प्रतिवादी

सिविल रिट पेटीशन नंबर 4378 ऑफ 1986

13 अप्रैल, 1987

इनकम-टैक्स एक्ट (१९६१ का अनुसूची XLII1)–धाराएँ 240, 241, 256(1)–जोखिम तैयार किया गया–ऐसे मूल्यांकन पर कर जमा किया गया–मूल्यांकन की निरस्ति–भुगतान किया गया कर की वापसी–उच्च न्यायालय में सन्दर्भ की प्रलंबितता–वापसी का रोक–ऐसे रोक के लिए कारण।

निर्णय, कि धारा 241 के तहत इनकम-टैक्स अधिकारी को, इनकम-टैक्स एक्ट, १९६१ के अनुसार उच्च न्यायालय में सन्दर्भ के प्रलंबन के दौरान, जो प्रत्यार्पण बन गई, जो प्रतिवेदक को होने वाली थी, उसे रोक सकता है, आयातकारी की पूर्व मंजूरी के साथ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा